(iv) Demand for a Central School at Ghazipur, U.P.

श्री जैनुल बशर(गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ओपीयम एण्ड अलकालेण्ड वर्क्स, गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है।

गाजीपुर में अच्छी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इनके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं में केन्द्रीय पुलिस बलों तथा अन्य केन्द्र सरकार की सेवाओं में गाजीपुर जिले के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बलों में काम करने वाले लोगों की तैनाती बहुधा ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर अपना परिवार नहीं रख सकते। अधिकतर ऐसा भी होता है कि कभी वे परिवार रख पाते हैं और कभी अपने घरों को वापस भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पुत्रों-पुत्रियों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय खुल जाने से ऐसे सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि अगले सत्र से गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की वह स्वीकृति प्रदान कर दे तथा इसकी पूरी व्यवस्था करे।

(v) Need to reorganise Trade Unions in Indian Railways

SHRI ERA AMBARASU (Chengalpattu) : There are two Federations in Railways *viz.* NFIR, affiliated to INTUC and AIRF, controlled by the Socialist Party. These are only federal bodies of recognized zonal railway unions.

The zonal unions are recognised unions and with this recognition, the office-bearers continue to hold the Unions in their control. They manipulate the membership and submit to Trade Union Registrar periodically to safeguard their registration. Some station masters, loco running staff etc. have formed category-wise unions. These unrecognised unions are also having more membership than recognised unions.

Those leaders of recognised federations and unions nominate their representatives from staff benefit fund committee to the Departmental and National Council level, without getting mandate of railwaymen. The zonal railway administration are not exercising any check, but simply accept lists of office-bearers without any verification of the credentials of the nominee. Hence, a high level committee should be formed to conduct elections at all levels in the trade unions in Indian Railways.

I urge upon the Minister to reorganise these unions by fair elections, which will bring one union for one industry to constitute a monitoring body, consisting of railway trade union leaders, railway officers, officials from the Labour Ministry and Consultative Committee Members of the Railway Ministry to conduct the elections.

(vi) Industrialisation of Jaunpur, U.P.

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, इससे पहले दो दफा पार्लियामेंट में अपनी कान्सटीटुयेन्सी जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार से मतालबा कर चुका हूं कि एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाए और सन् 1983 में यूनियन इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपने एक अखबारी बयान में कहा भी था कि जौनपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाएगी, जिससे मुझे और जौनपुर के तमाम लोगों को बड़ी मसर्रत हुई थी लेकिन 36 साल जिस तरह हमें सिर्फ वायदे ही वायदे मिलते रहे, वह ऐलान भी उन्हीं वायदों की फेहरिस्त में गुम हो गया।

जौनपुर में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने से जौनपुर का पिछड़ापन तो दूर होगा ही, साथ ही साथ बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान तबका मुजरीमाना जिन्दगी गुजारने पर मजबूर होता है

वह रोजगार मिल जाने की वजह से अच्छी जिन्दगी गुजारने का मौका पाएगा ।

मैं आज फिर जौनपुर के लोगों की तरफ से जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जौनपुर में बड़ी इन्डस्ट्री लगाई जाए ताकि जौनपुर का पिछड़ापन और बेरोजगारी दूर होने में मदद मिले और जौनपुर के लोगों को राहत मिले ।

(vii) Doordarshan facilities to Shahdol district of Madhya Pradesh

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, शहडोल जिला एक औद्योगिक प्रधान जिला है, जो मध्यप्रदेश के लगभग मध्य बिन्दु पर स्थित है । इस जिले में 20 कोयला खदानों का जाल बिछा है, जिससे 25 हजार टन कोयले का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है । इसके अतिरिक्त अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, पेपर मिल, सोडा फैक्ट्री, पॉटरीज फैक्ट्री एवं बाक्साइड का विशाल भंडार है ।

शिक्षा की दृष्टि से यह जिला अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें 7 महाविद्यालय आई० टी० आई० एवं माइनिंग पालिटेक्निक महाविद्यालय हैं, जो कि मध्यप्रदेश में एकमात्र है ।

रीवा संभाग का श्रम न्यायालय तथा सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय भी यहीं स्थित है । जनसंख्या की दृष्टि से यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यह लोकसभा, आदिवासियों के लिये सुरक्षित सीट है । बहुउद्देश्शीय बाण सागर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन बांध इस जिले का गौरव है, जिससे मध्यप्रदेश, बिहार एवं उत्तरप्रदेश को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।

बिरसिंहपुर पाली में निर्माणाधीन थर्मल पावर स्टेशन भी इसी जिले में स्थित है ।

केन्द्रीय शासन ने 1984 तक भारत के 65 प्रतिशत क्षेत्र में टेलीविजन का लक्ष्य बनाया है, किन्तु शहडोल जिला इससे अछूता है, जबकि आस-पास के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी ।

अतः भारत शासन से अनुरोध है कि आगामी विस्तार योजना में शहडोल जिले को सम्मिलित कर 15 अगस्त, 1984 से टेलीविजन का शुभारम्भ किया जाये ।

(viii) Termination of contract by Indian Iron and Steel Co. entered into with Damodar Cement Co. for the purchase of slag.

SHRI BASUDEB ACHARIA (Bankura) : The unilateral termination of long-term supply contract by Indian Iron and Steel Company Ltd. poses a threat to the existence of Damodar Cement, a CCI and Government of West Bengal joint enterprise, for which Industrial Development Bank of India has made 17 crore rupees loan commitment. It was in December 1980 that a deal was finalised between WBIDC and IISCO for supply of entire slag generated from latter's blast furnace at Burnpur. IISCO offered land and transportation facilities to the WBIDC for setting up of granulation plant and running it. The termination of contract may lead to the closure of Damodar Cement, resulting in heavy investment losses for CCI and West Bengal Government. The Company has already spent Rs. 2.5 crores and placed order for machinery and equipment to set up a large granulation plant at Burnpur and a cement plant in the district of Purulia. An expenditure of Rs. 6 crores has already been committed. I urge upon the Government to look into the matter.

(ix) Setting up of a Thermal Power Station at Valope or Dabhol (Ratnagiri)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : Survey for establishment of a thermal power station in Ratnagiri district of Maharashtra has been completed and report was submitted to the Government a year back. It is reported that two villages—Valope in Chiplum Taluka and Dabhol in Dapoli Taluka have been extensively surveyed in this connection. No further action has yet been taken in connection with the reports submitted to the Government.